भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1476

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

1476. श्री बाबू राम निषाद:

श्री तेजवीर सिंहः

श्री मयंककुमार नायकः

श्री बृज लाल:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

डा. संदीप कुमार पाठकः

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात सहित देश में अब तक पीएम गति शक्ति पोर्टल पर कितनी अवसंरचना परियोजनाओं का मानचित्रण और एकीकरण किया गया है तथा उनकी प्रगति और स्थिति क्या और;

(ग) जुलाई, 2025 में पैमाना पोर्टल के शुभारंभ के बाद से पीएम गति शक्ति ढांचे के अंतर्गत लागत वृद्धि दर्ज करने वाली परियोजनाओं की संख्या, उनकी प्रगति एवं वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनकी लागत वृद्धि का मूल्य तथा मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत सरकार द्वारा देश में त्वरित और समावेशी विकास के लिए एक प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, मजबूत, सतत और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सितंबर, 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी। एनएलपी का उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है, ताकि देश वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो

सके। डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से लॉजिस्टिक्स लागत के संबंध में किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी के लगभग 7.97% रहने का अनुमान है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य है।

(ख) और (ग): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी), जो देश में अवसंरचना की आयोजना और विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, अक्टूबर, 2021 में शुरू किया गया था। पीएमजीएस-एनएमपी फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी), केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, ताकि आयोजना के स्तर पर एकीकृत योजना, मल्टीमोडेलिटी, इंटर-मोडेलिटी, प्रयासों के तालमेल, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास, डेटा-आधारित निर्णय लेने आदि को सुनिश्चित किया जा सके। जून, 2026 तक, एनपीजी तंत्र के माध्यम से लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 396 अवसंरचना परियोजनाओं (गुजरात की 27 परियोजनाओं सहित) का मूल्यांकन किया गया है। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन 396 परियोजनाओं का मंत्रालय-वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की जारी परियोजनाओं की निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा एमओएसपीआई के पैमाना पोर्टल पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की जाती है। सभी चल रही अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का परियोजना-वार विवरण वेबसाइट https://paimana-proj.mospi.gov.in/ReportPage पर उपलब्ध है। पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की प्रगति/स्थिति की जानकारी पैमाना पोर्टल पर अलग से नहीं रखी जाती है।

*****

अनुबंध- क

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1476 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकन की गई परियोजनाओं का मंत्रालय-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर परियोजनाएं	मंजूर किया जाना है	कार्यान्वयन के तहत	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	171	108	63	53	9,01,668
रेल मंत्रालय	162	102	60	102	5,43,315
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	31	17	14	17	2,88,614
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4	4	0	3	9,271
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3	2	1	2	49,759
नागर विमानन मंत्रालय	6	4	2	2	10,005
एनआईसीडीसी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	12	12	0	12	28,693
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	01	1	0	1	20,774
इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	01	1	0	1	4,680
वस्त्र मंत्रालय	05	05	0	05	9,760
कुल	**396**	**256**	**140**	**198**	**18,66,539**

*****